मुख्य समाचार

- **सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को राहत–मुख्य संसदीय सचिव के पद से हटाए गए 6 विधायकों की सदस्यता नहीं होगी समाप्त।**
- **मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसले का किया स्वागत–कहा–आगामी रणनीति पर कानूनी राय लेगी सरकार।**
- **उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा जनसेवा और पिछड़े क्षेत्रों का उत्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।**
- **तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा–प्रदेश सरकार पढ़ाई के साथ–साथ खेलों को भी दे रही प्रोत्साहन।**

सी.पी.एस.मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के चलते मुख्य संसदीय सचिवों के पदों से हटाये गए कांग्रेस के सभी 6 विधायकों की सदस्यता बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार की एस.एल.पी. पर आज ये फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार फिर से सीपीएस की नियुक्ति नहीं कर सकती लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी और उनके खिलाफ फिलहाल अयोग्यता का मामला नहीं चलेगा। अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ विधायकों की अयोग्यता रद्द करने पर ही रोक लगाई है जबकि मुख्य संसदीय सचिवों को पद से हटाए जाने के हाई कोर्ट के फैसले पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने हाल ही के फैसले में मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्तियों से संबंधित हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2006 का कानून रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को काफी राहत मिली है।

सुक्खू

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा मुख्य संसदीय सचिव के पद से हटाए गए 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राहत महत्वपूर्ण है और प्रदेश सरकार सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद अगली रणनीति तय करेगी।

उन्होंने इस मामले पर विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की और कहा कि विपक्ष प्रदेश हित में काम करने के बजाए हर मामले पर राजनीति करने में मशगूल है। उन्होंने कहा कि हर मामले को विवाद के रूप में उछालना विपक्ष का स्वभाव बन गया है।

नरेश चौहान

मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के मंसूबों पर पानी फिर गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद भाजपा मुद्दा विहिन हो चुकी है और अब उसे अपने फैसलों पर आत्ममंथन करना चाहिए। नरेश

चौहान ने राज्य में पर्यटन विकास निगम के होटलों की खस्ताहालत के लिए पूर्व सरकार को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि निगम के ये होटल बीते दो सालों में ही घाटे में नहीं आए हैं बल्कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते पहले से ही घाटे में थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इन होटलों की स्थिति को बेहतर करने के लिए कार्य करेगी। प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद 9 होटलों को 31 मार्च 2025 तक खुला रखने की छूट दे दी है।

कर्ण नंदा

भाजपा के मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने प्रदेश की कांग्रेस की सरकार पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। कर्ण नंदा ने मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार द्वारा एक मीडिया कर्मी के खिलाफ की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कांग्रेस को मीडिया विरोधी करार दिया और कहा कि वह सच से भागने का काम करती है। भाजपा प्रवक्ता विवेक शर्मा ने भी इस घटना की निंदा की है।

चंद्र कुमार

पशु पालन व कुषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार बेसहारा पशुओं को आश्रय देने के लिए गौशाला बनाने को दी जाने वाली मदद को किसानों को भी प्रदान करने पर सरकार विचार कर रही है। चंद्र कुमार आज कुल्लू में किसान मेले के मौके पर मौजूद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बेसहारा पशुओं को किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान का समाधान ढूंढने के भी प्रयास कर रही है।

यादविंदर गोमा

आयुष व खेल मंत्री यादविंदर गोमा ने कहा है कि गांवों को सड़कों से जोड़ना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। गोमा आज जयसिंहपुर निर्वाचन क्षेत्र के पपरोला से आलमपुर को जोड़ने वाले पुल के शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है और इस दिशा में गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को पुल का निर्माण निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। इस पुल के निर्माण पर साढ़े आठ करोड़ रूपए खर्च होंगे।

अनुराग ठाकुर

सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार हताश व निराश है। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीपीएस का मामला अदालत में है और वहां से जो भी निर्देश होंगे वह सबको मान्य होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश हाई कोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को पहले ही असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और उसने लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने इससे पूर्व जनसमस्याएं भी सुनी और उसके बाद हमीरपुर जिला की दिशा कमेटी की बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की।

हर्ष वर्धन चौहान

उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन चौहान ने कहा है कि जनसेवा, जन समस्याओं का समाधान और पिछड़े क्षेत्रों व वर्गों का उत्थान कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर्ष वर्धन चौहान आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कफोटा में जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने अधिकांश समस्याओं को मौके पर ही समाधान किया। हर्ष वर्धन चौहान ने अधिकारियों को शेष समस्याओं का निर्धारित समय के भीतर

समाधान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा रखी गई मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा मंत्री

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पढ़ाई के साथ–साथ खेलों को भी प्रोत्साहन दे रही है। धर्माणी ने आज सरकाघाट में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज पुरूष बास्केट बॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कहा कि शैक्षणिक गतिविधियों के समान ही खेलकूद गतिविधियां भी आवश्यक है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का शारीरिक व मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रत्येक स्कूल में हर रोज कम से कम 15 मिनट का शारीरिक व्यायाम अनिवार्य किया है। प्रतियोगिता का खिताब डीएवी कॉलेज कांगड़ा ने जीता। जबकि आरएनटी कॉलेज सरकाघाट दूसरे और एचपीयू पीजी सेंटर शिमला तीसरे स्थान पर रहा।

संजय रत्न

विधायक संजय रत्न ने अधिकारियों से कहा है कि वे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पंचायत स्तर तक पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद और पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सके। संजय रत्न ने आज धर्मशाला में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सभी पंचायतों में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बोर्ड और जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में चालू वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा के 9687 नये मामलों को मंजूरी दी गई।

कमलेश ठाकुर

विधायक कमलेश ठाकुर ने कहा है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र की सभी विकासात्मक परियोजनाओं को चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाएगा। देहरा नंदपुर भटोली में आज जनसंपर्क अभियान के दौरान कमलेश ठाकुर ने कहा कि सरकार ने इस विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास का रोड़ मैप तैयार किया है और इसके अनुरूप विभागों को कार्य करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

बैडमिंटन

शिमला जिला स्तरीय मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 6 और 7 दिसंबर को शिमला में इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की जाएगी। शिमला जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर तुर्की और महासचिव सुमित धौटा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला व पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। यह प्रतियोगिता 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और 70 वर्ष आयु वर्ग में होगी। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी राज्य स्तर पर शिमला जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने सभी मास्टर बैडमिंटन खिलाड़ियों से इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।

संजौली मस्जिद

राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद विवाद को लेकर आज शिमला की ज़िला अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष की वैधता को लेकर वक्फ बोर्ड ने शपथ पत्र दायर किया। वक्फ बोर्ड ने अपने शपथ पत्र में मोहम्मद लतिफ को वर्ष 2006 से वक्फ बोर्ड कमेटी का अध्यक्ष बताया है। याचिकाकर्ता को इस पर ऐतराज है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ज़िला अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 नवम्बर को तय की है। इसी दिन अदालत याचिका पर अपना फैसला सुना सकती है। वक्फ बोर्ड के वकील ने सुनवाई के बाद कहा कि धारा 18 के तहत वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद लतिफ को मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष बनाया है और वह मस्जिद के प्रधान के तौर पर अधिकृत है। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के अधिवक्ता ने पूछा कि 18 साल से प्रधान चल रहे मोहम्मद लतिफ को क्यों नहीं

बदला गया जबकि वक्फ बोर्ड एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति 5 साल तक ही अध्यक्ष पद पर रह सकता है।

संजय अवस्थी

अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्प है। इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खासकर कमजोर वर्गों की आर्थिकी को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। संजय अवस्थी अर्की विधानसभा क्षेत्र की जघून पंचायत घर के लोकार्पण के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

मुख्य समाचार एक बार

- सुप्रीम कोर्ट से सुक्खू सरकार को राहत–मुख्य संसदीय सचिव के पद से हटाए गए 6 विधायकों की सदस्यता नहीं होगी समाप्त।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फैसले का किया स्वागत–कहा–आगामी रणनीति पर कानूनी राय लेगी सरकार।
- सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा–हिमाचल सरकार हताश व निराश।
- उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा जनसेवा और पिछड़े क्षेत्रों का उत्थान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।